PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 37 मंगलवार, अगस्त 18, 2026 विशाखापट्टनम संपादकः गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

शिक्षा के स्तर में सुधार से ही विकास संभवः मुख्यमंत्री चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 17 अगस्तः मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मेगा DSC भर्ती के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश विधानसभा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का विश्वास है कि अच्छी शिक्षा और कौशल प्रदान करने से विद्यार्थी उत्कृष्ट मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे।

उन्होंने कहा कि IT को बढ़ावा देकर आंध्र प्रदेश ने तकनीकी क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधनों में से कुछ तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने हमेशा शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है। एन.टी. रामा राव द्वारा आवासीय स्कूलों के माध्यम से किए गए सुधारों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी NTR ने ही की थी।

चंद्रबाबू ने कहा कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब स्कूलों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय, हर तीन किलोमीटर पर एक अपर–प्राइमरी स्कूल, प्रत्येक मंडल में एक जूनियर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार के बिना विकास संभव नहीं है। चंद्रबाबू ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 से 2024 के बीच बिना एक भी शिक्षक पद भरे सुधार करने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित 14 कैब में से 11 कैब के जरिए शिक्षक भर्ती ज्व्क सरकारों के दौरान हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने भी इन भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से ड्राई राशन भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में मिड–डे मील योजना तत्कालीन TDP सरकार ने शुरू की थी और बाद में इसे इंटरमीडिएट स्तर तक विस्तारित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है।

शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून बनाया गया, उन्होंने कहा। चंद्रबाबू ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में कई अभिनव सुधार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि SC और ST आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को IIT और IIM जैसी संस्थाओं में प्रवेश सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।

चंद्रबाबू ने दावा किया कि 2019 से 2024 के बीच करीब 10 से 12 लाख विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया था। इसी वजह से सरकार ने 'थल्लिकी वंदनम' योजना के तहत सभी बच्चों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के बाद एक लाख से अधिक विद्यार्थी निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आए हैं। उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अपने पांच साल के कार्यकाल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। मुख्यमंत्री ने बताया कि गठबंधन सरकार के सत्ता में आते ही उन्होंने पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए मेगा कैब के माध्यम से 15,941 पदों पर भर्ती की। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया महज 148 दिनों में पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। उन्होंने कहा कि ज्व्ज और कैब नोटिफिकेशन के साथ–साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी सावधानी से लागू की गई। 13 विषयों में 42,000 प्रश्नों का चयन कर सर्वोत्तम प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की गई। 154 केंद्रों पर CBT प्रणाली के जरिए परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम भी पारदर्शी तरीके से घोषित किए गए।

चंद्रबाबू ने कहा कि 15,941 उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया गया और उन्हें नियुक्तियां दी गईं। शिकायतों के समाधान के लिए जोनल समिति, राज्य स्तरीय समिति और अपीलीय प्राधिकरण भी गठित किए गए।

उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू नियमों का ही पालन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी पाने वाले सभी उम्मीदवार अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद रोजगार हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों ने स्वयं बताया कि मेगा कैब के माध्यम से उनकी मेहनत का फल मिला है। चंद्रबाबू ने कहा कि मेरिट–कम–रोस्टर प्रणाली के तहत समय–समय पर परिणाम जारी किए गए और पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन रही। उन्होंने सवाल किया, "इससे अधिक पारदर्शिता और कहां हो सकती है?"

मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त एक IAS अधिकारी और एक पूर्व मंत्री पर मनमाने ढंग से बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन में एक भी विचलन नहीं हुआ है।

चंद्रबाबू ने आरोप लगाया कि "मुकदमेबाज पार्टी" से जुड़े लोगों ने 300 से अधिक मामले दायर कर भर्ती प्रक्रिया में बाधाएं पैदा कीं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इन आरोपों पर आधिकारिक जानकारी के साथ पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कैब शिक्षक स्वयं इन आरोपों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने बताया कि कुरनूल और विजयवाड़ा में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने नारे लगाए कि वे बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी प्रतिभा को कमतर आंकने वालों को भी सबक सिखाएंगे।

चंद्रबाबू ने कहा कि गठबंधन सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि साजिश करने वाली पार्टियों और व्यक्तियों के प्रति।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो विधानसभा में आकर चर्चा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में आने पर बेनकाब होने के डर से कुछ लोग सदन में नहीं आ रहे हैं और बाहर "हिट एंड रन" की तरह राजनीति कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कैब के माध्यम से नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश में कोई साजिश कामयाब नहीं होगी और सभी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ की गई हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के साथ–साथ परीक्षाओं में भी और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कीचड़ उछालने की राजनीति पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी।

चंद्रबाबू ने YSRCP नेताओं पर विधानसभा में नहीं आने को लेकर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे बाहर PUBG खेल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को विधानसभा में आकर अपनी मांगें रखनी चाहिए। यदि उनकी बात तथ्यात्मक साबित होती है, तो सरकार उसमें सुधार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरे जीवन में यह पहली बार है कि मैंने ऐसी पार्टी देखी है जो ढाई साल से विधानसभा में नहीं आ रही है। विधानसभा में आए बिना वे वेतन ले रहे हैं और विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जनता के प्रति पूरी जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, यह जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भविष्य में परीक्षाओं को और अधिक मजबूत एवं पूरी तरह सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

विधानसभा में मंत्रियों के बीच मजेदार बातचीतय मंत्री सत्यकुमार पर लोकेश का चुटीला तंज

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 17 अगस्तः आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत में मंत्रियों के बीच हुई हल्की–फुल्की बातचीत दिलचस्प बन गई। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सत्यकुमार यादव भाजपा का गमछा पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस पर AP के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, "सत्यगारू.. आपको अलग से पार्टी का गमछा क्यों चाहिए? पूरी दुनिया जानती है कि आप भाजपा के हैं!"

लोकेश की टिप्पणी पर वरिष्ठ मंत्री किन्जारापु अच्चेन्नायडू भी मजाक में शामिल हो गए। उन्होंने सत्यकुमार की प्रशंसा करते हुए कहा, "हां सर.. सत्यगारू राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं में से एक हैं।" इससे वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो गया।

इसके बाद लोकेश ने एक बार फिर सत्यकुमार से मजाक करते हुए कहा, "हमारी पार्टी के लोगों को भी अनुशासन के बारे में सिखाइए।" इस दौरान पास बैठे एक ज्व्क विधायक ने कहा, "पार्टी फर्स्ट, सर!"

इस पर सत्यकुमार यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नेशन फर्स्ट.. पार्टी नेक्स्ट.. सेल्फ लास्ट!" सत्यकुमार की इस बात ने वहां मौजूद मंत्रियों और विधायकों को खूब प्रभावित किया और विधानसभा परिसर में हंसी–मजाक का माहौल बन गया। इस हल्की–फुल्की बातचीत से अलग–अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल और आपसी संबंध साफ नजर आए। अच्चेन्नायडू ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में सत्यकुमार की राजनीतिक अहमियत का उल्लेख किया, जबकि लोकेश का अपने खास अंदाज में मजाक करना इस बातचीत का विशेष आकर्षण रहा।

खास तौर पर सत्यकुमार का "नेशन फर्स्ट.. पार्टी नेक्स्ट.. सेल्फ लास्ट!" वाला बयान चर्चा का विषय बन गया। विधानसभा की कार्यवाही आमतौर पर राजनीतिक बहस और नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित रहती है, लेकिन इस दौरान हुई इस मजेदार बातचीत ने मंत्रियों और विधायकों के बीच हंसी के पल पैदा कर दिए।

"अपने राजनीतिक जीवन में ग्रुप–1 जैसा घोटाला कभी नहीं देखा": चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 17 अगस्तः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने YSRCP प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में APPSC ग्रुप–1 भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा की लॉबी में उनसे मिलने पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ग्रुप–1 जैसा घोटाला कभी नहीं देखा। उन्होंने दुख जताया कि इस कथित घोटाले में कई मेधावी विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं।

कैब में महिला शिक्षकों की संख्या अधिक

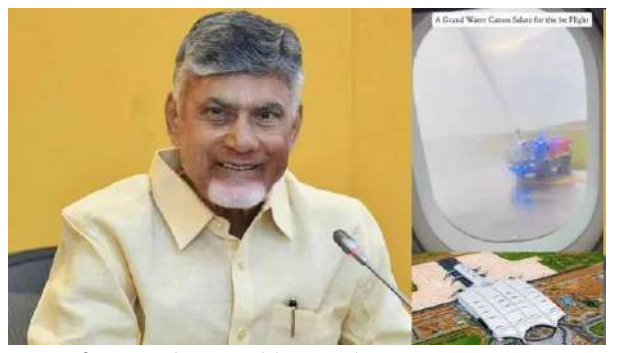

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले पर विधानसभा में परसों सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैब के जरिए बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। रविवार को विजयवाड़ा में शिक्षकों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षक अपने आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि YSRCP नेताओं द्वारा शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसे सहन नहीं कर पाने के कारण शिक्षक सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि महिला शिक्षकों का कैब और भर्ती प्रक्रिया के साथ भावनात्मक जुड़ाव है, जिसके कारण यह मुद्दा उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

मछली पकड़ने गए मछुआरे नहीं लौटे, कोनसीमा जिला प्रशासन अलर्ट

कोनसीमा, 17 अगस्तः मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए मछुआरों की नाव के वापस नहीं लौटने के बाद कोनसीमा जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉ. आर. महेश कुमार ने बताया कि अल्लवरम मंडल के ओडालारेवु फिश लैंडिंग सेंटर से संबंधित नाव IND&AP&E8&MO&135 इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गई थी। नाव को 13 अगस्त को ओडालारेवु वापस लौटना था, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं आई है। अधिकारियों के अनुसार नाव में कुल 8 मछुआरे सवार हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक नाव में 15 दिनों के लिए पर्याप्त राशन और करीब 1,000 लीटर डीजल मौजूद है। अधिकारियों का प्रारंभिक अनुमान है कि नाव विशाखापत्तनम या पारादीप के तटीय इलाकों की ओर गई हो सकती है। अधिकारियों ने मछुआरों से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को तुरंत इस मामले की जानकारी भारतीय तटरक्षक बल को देने और तलाश एवं बचाव अभियान शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला एसपी राहुल मीना के साथ समन्वय कर मछुआरों का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। कलेक्टर महेश कुमार ने नाव के मालिक और मछुआरों के परिवार के सदस्यों से पूरी आवश्यक जानकारी जुटाकर उसे तटरक्षक बल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि तलाश अभियान में मदद मिल सके।

भोगापुरम एयरपोर्ट पर पहली उड़ान पहुंचीय नए अध्याय की शुरुआतः मुख्यमंत्री चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 17 अगस्तः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भोगापुरम एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भोगापुरम एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है।

उन्होंने बताया कि अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से परिचालन शुरू हो गया है। हैदराबाद से पहली इंडिगो उड़ान भोगापुरम एयरपोर्ट पहुंची। पहली उड़ान के आगमन के साथ ही आंध्र प्रदेश ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि उत्तर आंध्र के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट राज्य में नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह हवाई अड्डा युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को नई उड़ान देगा तथा शिक्षा, रोजगार और कारोबार के अवसरों को और बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर आंध्र के विकास में भोगापुरम एयरपोर्ट की

महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने इसे आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यह उत्तर आंध्र के लिए एक नए प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के साथ आंध्र प्रदेश ने एक नए युग की शुरुआत की है।

उत्तर आंध्र के विकास में भोगापुरम एयरपोर्ट स्थायी मील का पत्थर बनेगाः उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण

अमरावती, 17 अगस्तः उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास को नई उड़ान देते हुए भोगापुरम अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से सेवाएं शुरू होना बेहद खुशी की बात है।

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन कल्याण ने कहा कि हैदराबाद से आई इंडिगो की उड़ान के सफलतापूर्वक उतरने के साथ ही यह राज्य के विकास के इतिहास में एक शानदार अध्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर निर्मित यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल परिवहन सुविधाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि उत्तर आंध्र के लोगों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं का साकार रूप है।

पवन कल्याण ने उम्मीद जताई कि इस हवाई अड्डे के कारण नए निवेश आकर्षित होंगे, औद्योगिक अवसरों में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी के अवसर और अधिक बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह उत्तर आंध्र के विकास में एक स्थायी मील का पत्थर साबित होगा।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक्स पर अपने पोस्ट में यह भी कामना की कि भोगापुरम अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक बने, यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान करे और दिन–प्रतिदिन प्रगति करता रहे।

विधानसभा में एल नीनो के प्रभाव पर चंद्रबाबू की अहम घोषणा

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 17 अगस्तः मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में एल नीनो का प्रभाव गंभीर है, जिसके कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्षा की तुलना में बारिश में भारी कमी दर्ज की जा रही है।

सोमवार को विधानसभा में एल नीनो पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विधानसभा के मंच से एल नीनो के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "गांवों के बीच, राज्यों के बीच और यहां तक कि देशों के बीच भी पानी को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं। जून से दिसंबर 2026 तक राज्य में 867 मिमी बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन अनुमान के अनुसार केवल 557 मिमी बारिश दर्ज हो सकती है। इस वर्ष सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में जुलाई महीने में 68 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई।

अगस्त में 35 प्रतिशत, सितंबर में 35 प्रतिशत, अक्टूबर में 25 प्रतिशत और नवंबर में 20 प्रतिशत बारिश की कमी रहने का अनुमान है।"

उन्होंने आगे कहा, "दिसंबर महीने में हालांकि सामान्य से 1 प्रतिशत अधिक बारिश होने की संभावना है। विभिन्न नदी घाटियों में पानी की उपलब्धता घट रही है।

संपादकीय

'रोजगार' बेहाल!

जुलाई में VB&G RAM G के तहत केवल 7.67 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार दर्ज हुआ, जबकि पिछले साल MGNREGA के तहत यह आंकड़ा 15.33 करोड़ था। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में 51: की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में शुरू की गई विकसित भारतदृगारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना के लागू होने के पहले ही महीने में ग्रामीण रोजगार सृजन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे नई रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन और उसकी पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

जुलाई 2026 में इस योजना के तहत केवल 7.67 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार दर्ज किया गया। इसकी तुलना जुलाई 2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दर्ज 15.33 करोड़ व्यक्ति–दिवस से करें तो यह करीब 50% कम है। रोजगार पाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या भी 1.42 करोड़ से घटकर 68.94 लाख रह गई, यानी 51-45% की गिरावट।

VB&G RAM G 1 जुलाई 2026 से लागू हुई और इसने डळछत्म्ळ। की जगह ली। नई योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सालाना रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार, रोजगार में कमी के पीछे कई कारण हैं। इनमें MGNREGA से नई व्यवस्था में बदलाव, कृषि कार्यों के चरम मौसम के दौरान रोजगार सृजन में विराम तथा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या में कमी शामिल है।

नई व्यवस्था के तहत राज्यों को बुआई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक रोजगार कार्य रोकने की अनुमति है। सरकार का मानना है कि इससे कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डळछत्म्ळ। में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि नई व्यवस्था में बदलाव सुचारु रूप से हुआ है। मंत्रालय के अनुसार, रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीण परिवारों में 98: से अधिक परिवारों को काम उपलब्ध कराया गया। मंत्रालय ने यह भी अनुमान लगाया है कि जुलाई में वास्तविक रोजगार सृजन करीब 9 करोड़ व्यक्ति–दिवस रहा।

लेकिन आलोचकों का कहना है कि मौसमी प्रतिबंध, तकनीकी नियम और पुरानी योजना से नई योजना में बदलाव के दौरान आई परेशानियां रोजगार के आंकड़ों में भारी गिरावट का कारण हो सकती हैं। श्रमिक संगठनों और आलोचकों के अनुसार, VB&G RAM G, MGNREGA की मांग–आधारित व्यवस्था से हटकर अधिक नियंत्रित और आपूर्ति–आधारित व्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देती है।

उनका कहना है कि कृषि कार्यों के मौसम में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने से उन मजदूरों को नुकसान हो सकता है जिनके पास रोजगार के वैकल्पिक अवसर बहुत कम हैं। डिजिटल सत्यापन और तकनीक आधारित क्रियान्वयन को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं। आलोचकों के मुताबिक, खासकर डिजिटल सत्यापन में कठिनाई झेलने वाले ग्रामीण मजदूरों के लिए ये नियम परेशानी पैदा कर सकते हैं।

VB&G RAM G में प्रमुख बदलावों में से एक वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। हालांकि, यह ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश से कम है। 12 मार्च 2025 को पेश अपनी रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति ने प्रत्येक परिवार के लिए गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कम से कम 150 दिन करने की सिफारिश की थी। समिति ने ग्रामीण संकट से निपटने के लिए डळछत्म्ळ। की व्यापक समीक्षा करने और इसके तहत किए जाने वाले कार्यों का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की थी। नई व्यवस्था में अकुशल मजदूरों के लिए एक समान मजदूरी दर तय करने की संभावना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि महंगाई के अनुरूप मजदूरी में नियमित संशोधन की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उनका चेतावनी है कि कीमतें बढ़ने के दौरान सूचकांक आधारित मजदूरी संशोधन नहीं होने पर ग्रामीण मजदूरों की वास्तविक आय घट सकती है।

आलोचकों के अनुसार, इससे गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाली योजना का प्रभाव कमजोर हो सकता है।

VB&G RAM G में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्र 90% खर्च वहन करेगा। अन्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात 60:40 होगा। फिस्कल मेमोरेंडम के अनुसार, मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्च सहित योजना का सालाना खर्च 1,51,282 करोड़ अनुमानित है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 95,692.31 करोड़ होगी, जबकि राज्यों पर करीब 56,000 करोड़ का भार पड़ेगा।

आलोचकों का कहना है कि सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्यों पर बढ़ी हुई हिस्सेदारी अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकती है। बारिश और कृषि परिस्थितियों को लेकर जारी चिंताओं के बीच ग्रामीण रोजगार में गिरावट का महत्व और बढ़ जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के करीब आधे जिलों में बारिश की कमी दर्ज की गई है, जबकि खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 26-50% घटा है।

जब कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ती है, तब ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आय की सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति–दिवसों में कमी इस सवाल को जन्म देती है कि क्या नई योजना ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त आय सहायता उपलब्ध करा पाएगी।

कुल रोजगार में कमी के बावजूद महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। कुल व्यक्ति–दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 63% रही, जो कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम एक–तिहाई से काफी अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि कुल रोजगार में भारी गिरावट के बावजूद यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए अब भी रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है।

VB&G RAM G के पहले महीने के नतीजे मिले–जुले रहे हैं। एक तरफ रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है और महिलाओं की भागीदारी भी काफी अधिक है। दूसरी ओर, व्यक्ति–दिवसों और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में भारी गिरावट ने योजना के क्रियान्वयन, पहुंच और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जुलाई में दर्ज गिरावट केवल मौसमी परिस्थितियों और MGNREGA से नई व्यवस्था में बदलाव के कारण हुई है या फिर नई योजना में इससे भी गंभीर संरचनात्मक समस्याएं हैंकृ यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा।

'सप्तधारा' साकार हो तभी प्रगति

15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के 13वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन को लेकर सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि इस बार उनका भाषण कैसा होगा। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण बने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलनों के बाद, सरकार का सामान्य रुख क्या होगा, इसका अनुमान इस भाषण के माध्यम से लगाने की उम्मीद की जा रही थी। सीजेपी, जेन–जेड के विरोध प्रदर्शन, उनके पीछे छिपे मूल कारण और अभी भी जारी असंतोष देश के लिए गंभीर चिंता के विषय बने हुए हैं। 75 मिनट के उनके भाषण में दो प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं। पहली बात यह थी कि सरकार वामपंथियों, आंदोलनकारियों और वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों के प्रति अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सलियों को भले ही पराजित कर दिया गया हो, लेकिन नक्सली विचारधारा अभी भी मौजूद है। इसी संदर्भ में उन्होंने 'दिमागी नक्सल' नाम का एक नया भय सामने रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को व्यवस्था से बाहर करने की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी ताकतें अवसरों की तलाश में हैं और हिंसा तथा अराजकता की ओर ले जाने वाले रास्ते खोजते हुए समाज को गुमराह करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपना रही हैं। दूसरी ओर, युवाओं, विशेषकर बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगाने के लिए उन्होंने 'सप्तधारा' के नाम से सात प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख किया। यह भाषण विशेष रूप से देश के युवा नागरिकों को संबोधित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े सपने देखना, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना और तेजी से क्रियान्वयन करना आवश्यक है। देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग के लिए तैयार करने के लिए अगले वर्ष एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया। परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नवाचार, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष क्षेत्र, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी उन्होंने दोहराया। इसमें ड्रोन और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास भी शामिल है। ये आश्वासन भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और देश को आगे ले जाने के संकल्प को दर्शाते हैं और प्रत्येक भारतीय स्वाभाविक रूप से इनका स्वागत करेगा। हालांकि, इन लक्ष्यों और चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता जताई या इसके लिए प्रयास किया, यह सवाल बना हुआ है। देश में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हर वर्ष हासिल हुई प्रगति आने वाले वर्षों में और तेज होनी चाहिए तथा उसका समग्र प्रभाव दिखाई देना चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यभार संभालने से पहले और उसके बाद हासिल उपलब्धियों की केवल पूर्ण आंकड़ों के आधार पर तुलना करना सांख्यिकीय दृष्टि से उचित नहीं है। राजनीतिक रूप से भी ऐसा करना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा करता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का सामना करने के बाद भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ऐसे समय में देश के सामने पहले से कहीं अधिक असाधारण चुनौतियां हैं। एक ओर बड़ी संख्या में युवा आबादी रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। दूसरी ओर तकनीकी ज्ञान हमारे जीवन जीने के तरीके और कामकाज को पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए सभी को साथ लेकर चलने वाली एक समग्र नीति अत्यंत आवश्यक है। चुनाव जीतने की होड़ और राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों और वर्गों के बीच आम सहमति से बनी राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। देश जिन असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनसे निपटने के लिए सभी को एक ही दिशा में और मिल–जुलकर काम करने की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। विकसित देशों को अब तकनीकी पूंजीवाद झकझोर रहा है। तकनीकी पूंजीवाद तकनीक और पूंजीवादी व्यवस्था के मेल से बनी आधुनिक आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था है। इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरकर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके कारण अत्यधिक लाभ कुछ कंपनियों और निवेशकों के बीच अधिक मात्रा में केंद्रित हो सकता है। हमें इस तकनीकी पूंजीवाद की नकल करने की कोशिश करने के बजाय अपने देश की परिस्थितियों, जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप अपना विकास मॉडल तैयार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में इसी मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी इन चुनौतियों को स्पष्ट रूप से पहचानते हुए भी अपने आलोचकों को दुश्मन मानते हुए दिखाई देते हैं। विभाजन की ओर ले जाने वाली मतभेदों की खाइयों को और गहरा करने के बजाय, अलग–अलग विचारों को सुनने और उन्हें समझने के तरीकों को व्यवहार में लाने से ही अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लाल किले की गवाही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आश्वासन यदि बेहतर शिक्षा, अच्छे रोजगार, अधिक आय और आर्थिक प्रगति के अवसरों में तब्दील नहीं होते हैं, तो वे केवल राजनीतिक वादे बनकर रह जाएंगे। वे वामपंथी विचारधाराओं के विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे।

कमल दल में उथल–पुथल!

उपचुनावों में हार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण बने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद भाजपा के खेमे में यह राय आम होती जा रही है। कहा जा सकता है कि उपचुनावों के नतीजे ऊंची जातियों की ओर से आई चेतावनी हैं, विद्रोह नहीं। आखिर उपचुनावों में ऊंची जातियों के वोटों का रुख किस तरह बदला? नितिन नबीन और उससे पहले उनके पिता का गढ़ रहे बांकीपुर का नतीजा निस्संदेह सबसे चौंकाने वाला है। कायस्थ, ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की बड़ी संख्या वाले इस क्षेत्र को बिहार में भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है।

पिछले डेढ़ दशक से भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों में पूरी तरह हावी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहली बार संसद सत्र में भाग लेने से पीछे हटते नजर आए। पश्चिम बंगाल चुनाव में दो–तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के बाद भाजपा ने जश्न मनाया था कि अब देश में उसे कोई चुनौती नहीं है। इन दोनों नेताओं ने संसद सत्र के लिए व्यापक तैयारियां की थीं। टीएमसी, आप और एनसीपी (एसपी) जैसे दलों के सांसदों को तोड़कर संसद में दो–तिहाई बहुमत हासिल करने की दिशा में उत्साहपूर्वक कदम बढ़ाए गए। पिछले अप्रैल में विफल रहे परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों को फिर से लाकर उन्हें पारित कराने की भी तैयारी थी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट हो गई। विवादास्पद विधेयकों को इन सत्रों में पारित कराना तो दूर, युवाओं के आंदोलन के आगे झुकते हुए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने एक मंत्री को पद से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का सत्र चला, लेकिन आखिरी दिन को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सदन में नजर नहीं आए। अंतिम दिन औपचारिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद उन्होंने चुप्पी साधे रखी। छोटे–मोटे विधेयक भले ही पारित हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण विदेशी अंशदान नियमन विधेयक को पारित कराने का साहस वे नहीं जुटा सके और उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजकर मामले को टाल दिया। नंबर एक और नंबर दो नेता विपक्ष और छात्रों का सामना नहीं कर पाए और संसद से दूरी बनाए रखी। दोनों नेताओं को इतनी असहज स्थिति का सामना केवल नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के कारण नहीं करना पड़ा। इसी दौरान हुए तीन विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी उन्हें एक तरह से झटका दिया।

बिहार में, जहां भाजपा तीन दशकों से अधिक समय से लगातार मजबूत प्रदर्शन करती रही है, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा खाली की गई बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत ने भाजपा के लिए एक चेतावनी का काम किया। इससे यह संकेत मिला कि दशकों से पार्टी के 'कोर वोटर' रहे ऊंची जातियों के लोग भाजपा से नाराज हैं। सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी जगह–जगह आरक्षण विरोधी भावनाएं सामने आईं। इससे संकेत मिला कि ये वर्ग मोदी और अमित शाह द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित 'बीसी, ओबीसी' प्राथमिकताओं से नाराज हैं। वास्तव में बीसी और ओबीसी वर्गों को केवल 'सजावटी' पद दिए जा रहे हैं। पार्टी और सरकार में निर्णायक शक्तियां अब भी ऊंची जातियों के नेताओं के हाथों में हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों को चलाने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण अधिकारी भी अधिकांशतः ऊंची जातियों से हैं। केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इन्हीं के नियंत्रण में हैं।

दूसरी ओर, 2014 से पहले पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे नेताओं को लगातार पीछे किया जाना और दूसरी पार्टियों से आए, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को ऊंचे पदों पर पहुंचाया जाना पार्टी के 'कोर वोटरों' में गहरा असंतोष और नाराजगी पैदा कर रहा है। 'आत्ममंथन का समय' कहते हुए हाल के उपचुनावों में भाजपा की हार के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 'एक्स' पर जो पोस्ट किया, वह शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। चूंकि वह ग्वालियर के राजघराने से आती हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाली दतिया सीट की हार के संदर्भ में ही यह टिप्पणी की होगी। लेकिन दतिया उपचुनाव के साथ–साथ बांकीपुर का भी विशेष रूप से उल्लेख करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका ध्यान राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर है।

उपचुनावों में हार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण बने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद भाजपा के भीतर यह राय आम होती जा रही है। कहा जा सकता है कि उपचुनावों के परिणाम ऊंची जातियों की ओर से आई चेतावनी हैं, विद्रोह नहीं। उपचुनावों में ऊंची जातियों के वोटों का रुख कैसे बदला? नितिन नबीन और उससे पहले उनके पिता का गढ़ रहे बांकीपुर का परिणाम निस्संदेह सबसे चौंकाने वाला है। कायस्थ, ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की बड़ी संख्या वाले इस क्षेत्र को बिहार में भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत हासिल करके बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच पारंपरिक रूप से कड़े मुकाबले वाली मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा की हार के पीछे भी ऊंची जातियों के मतदाताओं का समर्थन बदलना और भाजपा के प्रमुख नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में व्याप्त असंतोष को कारण माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ऊंची जातियों के असंतोष का सामना कर रही है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी और आय में वृद्धि नहीं होना ऊंची जातियों की नाराजगी का प्रमुख कारण है। ऊंची जातियों के लोग खुले तौर पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं कि भाजपा केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाओं से लाभ पाने वाले बेहद गरीब लोगों के बारे में सोचती है। आरक्षण विरोधी एक कार्यकर्ता ने कहा, "सामान्य वर्ग के लिए भाजपा की आखिरी नीति ईडब्ल्यूएस कोटा थी, जिसे जनवरी 2019 में लाया गया था। वह भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान हमें उचित सबक सिखाने के बाद ही लागू की गई।"

ऊंची जातियों का असंतोष केवल इन उपचुनावों तक सीमित नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में 29 वर्षीय रविंद्र सिंह भाटी के प्रवेश को भी राजपूत समाज के असंतोष की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता भाटी ने संगठन से मतभेद के बाद स्वतंत्र रूप से छात्र चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2023 में भाटी ने बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। इसके परिणामस्वरूप भाजपा चौथे स्थान पर चली गई। इसके बाद भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और 5.8 लाख वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में राजपूत मतदाता लगभग पूरी तरह भाजपा से दूर हो गए। उत्तराखंड में आशीष नेगी नामक एक मुखर युवा नेता उत्तराखंड क्रांति दल के पुनरुद्धार का नेतृत्व कर रहे हैं। भूमि, रोजगार और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना नेगी का प्रमुख मुद्दा है। उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों के हितों को दांव पर लगाकर भाजपा सरकार बाहरी लोगों को लाभ पहुंचा रही है। हालांकि, सौभाग्य से ऊंची जातियों के लोग भी काफी हद तक यह स्वीकार करते हैं कि भाजपा के अलावा उनके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं है। उनके अनुसार, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले दलों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह इसी नीति का अनुसरण कर रही है। इसलिए उम्मीदवारों के आधार पर केवल कुछ खास सीटों पर ही कांग्रेस एक विकल्प के रूप में दिखाई देती है। दतिया में भी यही हुआ। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर ऊंची जातियों के युवाओं के एक वर्ग में आम आदमी पार्टी ने रुचि पैदा की थी, लेकिन 2025 में दिल्ली में हार के बाद यह रुचि कम हो गई। अब प्रशांत किशोर की जीत ने इस वर्ग में, खासकर सोशल मीडिया पर और बिहार के बाहर भी, व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। अपनी जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर आलोचना करने और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के साथ प्रशांत किशोर रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी का सीएम हेमंत को पत्र

युवा देश का भविष्य, उनकी मांगें जायज

रांची, 17 अगस्त (एजेंसियां)। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी बाकी चिंताओं का समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

'शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ'

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन का माध्यम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था अब वैसी मजबूत ज्ञान-व्यवस्था नहीं रही, जैसी एक दशक पहले हुआ करती थी।

'छात्रों की मांगें जायज हैं'

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि झारखंड में छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण है और उनकी मांगें जायज हैं। उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से छात्रों के साथ बातचीत शुरू किए जाने की सराहना भी की।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के माध्यम से छात्रों से बातचीत शुरू की गई है और छात्रों की कई मांगों पर सहमति भी बनी है। हालांकि, इसके बावजूद आंदोलन जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

'आप छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलिए'

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वह स्वयं आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत मुलाकात से छात्रों की बाकी चिंताओं को दूर करने और सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश का भविष्य हैं। ऐसे संकट के समय में उनके साथ एकजुटता दिखाना और उनका समर्थन करना जरूरी है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से छात्रों की बात सुनने और इस पूरे मामले का समाधान निकालने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की।

पुतला दहन के बाद सरकार ने फिर बातचीत के लिए बुलाया

रांची में छात्रों का आंदोलन पिछले 20 दिनों से अधिक समय से जारी है। 16 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले दहन किए थे। इसके बाद झारखंड सरकार ने छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और छात्रों के बीच पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। आंदोलन के लिहाज से 17 अगस्त की बैठक को अहम माना जा रहा है।

पीजीआरएस शिकायतों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें: कलेक्टर

विशाखापत्तनम, पेन पावर, 17 अगस्त: जिला कलेक्टर एम. अभिषिक्त किशोर ने अधिकारियों को पीजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सोमवार को शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के बाद अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर समाधान की पुष्टि करनी चाहिए। कलेक्टर ने स्वयं कई शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनकी शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को अस्थायी समाधान देने के बजाय शिकायतों के मूल कारणों की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों को शिकायतों के निवारण से पहले और बाद की जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने, उचित अनुमोदन एवं प्रमाण–पत्र जारी करने तथा पारदर्शिता के लिए सीधे प्राप्त होने वाले आवेदनों को भी पीजीआरएस पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से कहा गया कि वे शिकायतों को दोबारा खुलने से रोकें और बार–बार दोबारा खुलने वाली शिकायतों पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने तथा नागरिक संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर विशेष ध्यान देते हुए पीजीआरएस रैंकिंग में शीर्ष पांच में स्थान बनाए रखने का प्रयास करने का निर्देश दिया।

रिज्यूमे से इंटरव्यू तक... करियर सफलता का मार्ग

गंडेपल्ली, 17 अगस्त (पेन पावर): बदलते रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को अपने कौशल विकसित कर नौकरी के अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा मानव क्षमता आकलनकर्ता, मेंटर एवं कोच डॉ. अरुण मणि ने कहा।

सूरमपालेम स्थित आदित्य विश्वविद्यालय में "रिज्यूमे से इंटरव्यू तक दृ करियर सफलता की राह" विषय पर आयोजित विशेषज्ञ व्याख्यान में उन्होंने कहा कि रिज्यूमे केवल योग्यताओं की सूची नहीं, बल्कि रोजगार के अवसरों का द्वार खोलने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने इंटरव्यू में आत्मविश्वास, ईमानदारी, आत्म–जागरूकता और संवाद कौशल को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ब्रांड बनाने और नौकरी की तलाश में लिंक्डइन का प्रभावी उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बी. श्रीनिवास, डिप्टी प्रो–वाइस चांसलर डॉ. एम. श्रीनिवास रेड्डी, प्रो–वाइस चांसलर डॉ. ए. रमेश और डीन (करियर डेवलपमेंट) डॉ. संजीव राव सहित विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

सरकारी अधिकारियों को आम लोगों से नियमित तौर पर मिलना चाहिए : राजनाथ सिंह

नई दिल्लीनई दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसियां)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सरकारी अधिकारियों को नियमित रूप से आम लोगों के बीच जाना चाहिए। लोगों से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं को सुनने से अधिकारियों को जमीनी स्तर की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में लोक सेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी 'सेवा भावना' के साथ करें और लोगों को सुविधाजनक, संवेदनशील तथा जनहितैषी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दें।

हिमंत का कांग्रेस पर हमला

सोनिया-राहुल पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप, चिदंबरम को बताया 'पक्का नक्सली'

नई दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसियां)। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर शुरु हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि चाहे सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी, दोनों ने देश के खिलाफ काम करने का मिशन अपना लिया है। सरमा के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने देश का माहौल खराब करने की ठान ली है। उन्होंने वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि इससे साफ हो जाता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश का क्या हाल होगा।

सोनिया गांधी के व्यवहार पर उठाए सवाल

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी का व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति देश के माहौल को खराब करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरमा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में देश के सामने गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप

असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर खुले तौर पर देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लोगों को विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरमा के अनुसार, ऐसी गतिविधियां देश के हित में नहीं हैं और इनसे सामाजिक तथा राजनीतिक माहौल प्रभावित होता है।

चिदंबरम को लेकर भी साधा निशाना

हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पी. चिदंबरम केवल 'दिमागी नक्सल' नहीं, बल्कि पक्के नक्सली हैं। सरमा ने यह टिप्पणी चिदंबरम के उस कथित बयान के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने खुद को 'दिमागी नक्सल' बताया था। सरमा ने कहा कि जब देश के गृह मंत्री रह चुके पी. चिदंबरम ने खुद को 'दिमागी नक्सल' कहा है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके गृह मंत्री के कार्यकाल के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में कहीं जान-बूझकर लापरवाही तो नहीं बरती गई थी।

एआई युग में इंजीनियरिंग करियर के अवसरों पर जागरूकता

गंडेपल्ली, 17 अगस्त (पेन पावर): आदित्य विश्वविद्यालय, सूरमपालेम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा "एआई युग में इंजीनियरिंग करियर" विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें तृतीय वर्ष के लगभग 120 आईटी विद्यार्थियों ने भाग लिया। नेक्स्ट लेवल एडटेक के संस्थापक भीमा शंकर ने विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में इंजीनियरिंग क्षेत्र में उभर रहे नए करियर अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बदलती तकनीक के अनुरूप विद्यार्थियों को अपने कौशल लगातार विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई आधारित उद्योग में तकनीकी, व्यावसायिक और एआई संबंधी कौशल की मांग बढ़ रही है। विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग पर ध्यान देने के साथ–साथ समय रहते करियर की योजना बनानी चाहिए, ताकि वे एआई आधारित रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

कलेक्टर ने शिकायतों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

ओंगोल, 17 अगस्त: प्रकाशम जिला कलेक्टर पी. राजाबाबू ने अधिकारियों को 'मीकोसम' कार्यक्रम के तहत प्राप्त शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सोमवार को प्रकाशम भवन में आयोजित कार्यक्रम में कुल 284 शिकायतें प्राप्त हुईं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं क्षेत्र का दौरा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। निर्धारित समय में उचित समाधान उपलब्ध कराने तथा जिन मामलों का समाधान संभव न हो, उनके कारण आवेदकों को स्पष्ट रूप से बताने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर कल्पना कुमारी, डीआरओ पी. वेंकटरमण सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

दोस्त नदी में डूबा, मदद के बजाय फिल्म देखने चले गए दोनों साथी

सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी क्यों किया बरी ?

नई दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। उनका दोस्त नदी में डूब गया था। दोनों उसे बचाने की कोशिश किए बिना वहां से चले गए और फिल्म देखने चले गए। अदालत ने कहा कि उनका यह व्यवहार गलत और निंदनीय जरूर था, लेकिन केवल इसी आधार पर हत्या साबित नहीं की जा सकती।

निचली अदालत से हाई कोर्ट तक उम्रकैद

मामला 17 जुलाई 2006 का है। अभियोजन के मुताबिक, दोनों आरोपी अपने दोस्त को सुबह घर से यह कहकर ले गए थे कि उन्हें वॉलीबॉल खेलने के लिए अंकलेश्वर जाना है। बाद में वे नदी के पास पहुंचे। शाम तक दोस्त घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर बताया कि वह फिल्म देख रहा था और मृतक को पहले ही सहारा दरवाजा छोड़ चुका था। बाद में नदी किनारे मिले कपड़ों की पहचान मृतक के रूप में हुई। दोनों आरोपी बाद में मृतक के घर पहुंचे और बताया कि वे नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान उनका दोस्त डूब गया। उन्होंने कहा कि घबराकर वे वहां से भाग गए और बाद में फिल्म देखने चले गए। अगले दिन मृतक का शव मिला। पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबने से दम घुटना बताया गया था। इसके बावजूद निचली अदालत ने दोनों को हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में उम्रकैद की सजा दी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी दोषसिद्धि बरकरार रखी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हादसे की संभावना ज्यादा मजबूत

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि मौत हत्या थी। अदालत ने पोस्टमार्टम और डॉक्टर की गवाही का हवाला देते हुए कहा कि मृतक के शरीर पर मिली चोटें नदी में नहाते समय या पानी के बहाव में किसी कठोर वस्तु से टकराने के कारण भी हो सकती थीं। अदालत ने यह भी कहा कि कथित टूटी सोडा बोतल को डॉक्टर के सामने पेश नहीं किया गया और न ही खून लगे कांच के टुकड़े की विश्वसनीय बरामदगी या फोरेंसिक जांच सामने आई।

'फिल्म देखने जाना' हत्या का सबूत नहीं

पीठ ने हाई कोर्ट की उस धारणा से भी असहमति जताई कि जो व्यक्ति अपने दोस्त को डूबते देखे, वह फिल्म देखने नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसानी दिमाग चंचल, चालाक और कल्पनाशील होता है। मुश्किल परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के गलत या मूर्खतापूर्ण व्यवहार का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आरोपियों का घटनास्थल से भागना, मदद नहीं मांगना और बाद में फिल्म देखने जाना निंदनीय तो है, लेकिन इसे हत्या साबित करने वाला सबूत नहीं माना जा सकता।

अदालत ने दोनों को किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में निर्दोष होने की संभावना पूरी तरह बनी हुई है और उपलब्ध परिस्थितियां पहले से सोची-समझी हत्या के बजाय हादसे की ओर इशारा करती हैं। अदालत ने निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पलट दिए और दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

जनता की संतुष्टि ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मुख्य पैमाना

काकीनाडा, पेन पावर, 17 अगस्त: जिला कलेक्टर एम. एस. हरेंधीर प्रसाद ने कहा कि जनता की संतुष्टि अधिकारियों के प्रदर्शन का प्राथमिक पैमाना होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पीजीआरएस और राजस्व क्लिनिक से संबंधित याचिकाओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में पिछली शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रत्येक याचिका की क्षेत्र स्तर पर जांच करने, शिकायतकर्ताओं से बातचीत करने तथा निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतों का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, ताकि वे दोबारा न खुलें और शिकायतकर्ताओं को बार–बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि किसी शिकायत का समाधान संभव नहीं है, तो अधिकारियों को उचित प्रमाण–पत्र के माध्यम से उसका स्पष्ट कारण बताना चाहिए। कलेक्टर ने लापरवाही या गलत प्रमाण–पत्र जारी करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य स्तर की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और बिना किसी देरी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यश की 'टॉक्सिक' को सेंसर बोर्ड से मिली 'ए' सर्टिफिकेट की मंजूरी! कितने घंटे की होगी फिल्म

हाल ही में फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गईं। अब फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।

कितने घंटे की होगी फिल्म?

डायरेक्टर गीतू मोहनदास की इस पैन इंडिया एक्शन फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'A' सर्टिफिकेट मिलने की बात कही जा रही है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने फिल्म के जिस वर्जन को पास किया है, उसकी लंबाई करीब 3 घंटे 14 मिनट बताई जा रही है। यानी फिल्म काफी लंबी होने वाली है।

सूत्रों की मानें तो 'टॉक्सिक' की कहानी गोवा के बैकग्राउंड पर आधारित है। हालांकि, फिल्म की कहानी और लोकेशन को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

क्या है 'टॉक्सिक' की कहानी?

ट्रेलर के मुताबिक फिल्म की कहानी एक बाप और बेटे की लड़ाई पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत में एक बेटा अपने बाप से माफी मांगता है और आगे जाकर यही बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा नजर आता है। अब क्या है दोनों की कहानी यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा।

फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज डेट

फिल्म में यश लीड रोल में नजर आएंगे, जो राया का किरदार निभा रहे हैं। कियारा 'नादिया' का किरदार निभा रही हैं। वहीं तारा सुतारिया 'रबेका' और हुमा कुरैशी 'एलिजाबेथ' के किरदार में नजर आएंगी। इनके अलावा नयनतारा, रुक्मिणी वसंत समेत और भी कलाकार फिल्म में नजर आएंगे। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रश्मिका मंदाना ने अंडरवॉटर एक्शन सीक्वेंस में दिखाया दम

रश्मिका मंदाना ने बहुत कम समय में साऊथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बना ली है। 'पुष्पा' की श्रीवल्ली से लेकर 'एनिमल' की गीतांजलि तक, अभिनेत्री ने अलग-अलग किरदारों से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई है।

लेकिन इस वक्त रश्मिका जिस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वह है उनकी आगामी फिल्म 'मायसा' का एक बेहद चुनौतीपूर्ण अंडरवॉटर एक्शन सीक्वेंस, जिसे मेकर्स भारतीय सिनेमा का पहला फीमेल लीड अंडरवॉटर फाइट सीक्वेंस बता रहे हैं । इस खतरनाक और अनोखे स्टंट ने उसके करियर में एक नया मील का पत्थर जोड़ दिया है।

पानी के अंदर 20 घंटे का खतरनाक एक्शन, बिना बॉडी डबल के

'मायसा' के लिए रश्मिका ने जो अंडरवॉटर सीक्वेंस शूट किया है, वह किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेत्री ने करीब दो दिनों में लगभग 20 घंटे पानी के अंदर रहकर इस सीक्वेंस को पूरा किया।

सबसे खास बात यह है कि उसने इस पूरे स्टंट के लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया और सभी एक्शन खुद ही किए।

फिल्म के निर्देशक रवींद्र पुले ने सोशल मीडिया पर शूटिंग की कुछ झलकियां साझा कीं, जिनमें रश्मिका 'वैटसूट' (गोताखोरी वाली ड्रैस) में नजर आ रही है और उसके आसपास गोताखोर मौजूद हैं। तस्वीरों में वह पानी के अंदर सीक्वेंस को लेकर दिए जा रहे निर्देशों को बेहद ध्यान से सुनती दिखाई देती है । एक अन्य तस्वीर में उसके किरदार की पीठ पर चोट के निशान भी नजर आते हैं, जो इस एक्शन की तीव्रता को दर्शाते हैं।

निर्देशक ने इस सीक्वेंस को भारतीय सिनेमा के लिए एक अनोखा अनुभव 'बताते हुए कहा कि दर्शक पहली बार पानी की गहराइयों के अंदर

एक महिला किरदार को इस तरह की लड़ाई करते देखेंगे।

अब तक के मेरे करियर की सबसे मुश्किल चुनौती

रश्मिका ने भी इस अनुभव को अपने करियर का सबसे कठिन लेकिन रोमांचक हिस्सा बताया है। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह उसके जीवन का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन इसी चुनौती ने उसे सबसे ज्यादा उत्साहित भी किया। लगभग 20 घंटे पानी के अंदर शूटिंग करना सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद कठिन होता है। ऐसे सीक्वेंस में सांसों पर नियंत्रण, पानी के दबाव में मूवमैंट और लगातार फोकस बनाए रखना जरूरी होता है ।रश्मिका का बिना बॉडी डबल के इस स्टंट को पूरा करना यह दिखाता है कि वह अपने किरदारों के लिए लगातार सीमाएं तोड़ने को तैयार हैं।

दिखेगा रश्मिका का बिल्कुल अलग अवतार 'मायसा' का निर्देशन रवींद्र पुले कर रहे हैं और इसे अनफॉर्मूला फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है । फिल्म को आदिवासी पृष्ठभूमि पर आधारित एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है। यह रश्मिका की पहली फीमेल लीड पैन-इंडिया एक्शन फिल्म है। रिलीज हो चुके फिल्म के फर्स्ट लुक में रश्मिका का बेहद आक्रामक और उग्र अवतार देखने को मिला था- खून से सना चेहरा, हाथ में हथियार और आंखों में गुस्सा । इस लुक ने पहले ही संकेत दे दिया था कि यह फिल्म उसके करियर की सबसे अलग और दमदार फिल्मों में से एक होने वाली है। फिल्म के इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है और इसका टीजर जल्द जारी किया जा सकता है।

कई भाषाओं की फिल्मों में कर रही है काम

रश्मिका इन दिनों भारतीय सिनेमा की व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल है। वह हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के और वह करीब 30 नैशनल और अनुसार, उसके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनैशनल ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है। वह हाल ही में फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थी।

डांस सीन फिल्माते हुए लगी चोट

दूसरी ओर रश्मिका 'मायसा' की शूटिंग के दौरान एक डांस सीक्वेंस फिल्माते हुए चोटिल हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, डांस और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उसके कूल्हे में चोट लगी है।

रश्मिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी है। रश्मिका ने बताया कि वह कुछ समय से सोशल मीडिया से दूर थी और अब अपनी चोट के बारे में फैंस

को जानकारी दे रही है। उसने लिखा कि चोट लगना बिल्कुल भी अच्छा अनुभव नहीं है । रश्मिका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह उम्मीद कर रही थी कि किसी को उसकी चोट के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अब जब सबको पता चल ही गया है तो वह वापस आ गई है।

रश्मिका ने बताया कि उसे यह चोट कुछ समय पहले लगी थी और यह उसकी लगातार तीसरी चोट है। उसने कहा कि उसे अपने शरीर को मशीन की तरह नहीं, बल्कि इंसानी शरीर की तरह ट्रीट करना सीखना चाहिए ।

मेरी चिंता मत करना

रश्मिका ने फैंस को भरोसा दिलाया कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने बताया कि दर्द जरूर है, लेकिन वह इसे सहन कर पा रही है। मजाकिया अंदाज में उसने कहा कि शायद भगवान उसे यह समझा रहे हैं कि अगर वह खुद ब्रेक नहीं लेगी तो उसे जबरन आराम करना पड़ेगा। रश्मिका ने बताया कि फिलहाल वह अपना समय पहेलियां हल करने में बिता रही है और उसे खुद नहीं पता था कि वह इसमें इतनी अच्छी है।

सोनू निगम ने खोला सिंगिग का राज, ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल पर बोले- 'खुशकिस्मत हूं मैं'

सिंगर सोनू निगम ने कहा है कि वह कुछ चुनिंदा गानों के लिए ऑटो-ट्यून का इस्तेमात करते हैं। इसके साथ ही सोनू ने ऑटो-ट्यून के असली उद्देश्य पर भी चर्चा की।

सोनू क्यों करते हैं ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल?

सोनू हाल ही में यूट्यूब पॉडकास्ट गेम चेंजर्सः द म्यूजिक सीरीज पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा, 'मैं कुछ चुनिंदा गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करता हूं। डिजिटल रिकॉर्डिंग से कभी-कभी असली आवाज थोड़ी बेसुरी लग सकती है।' बातचीत के दौरान ऑटो-ट्यून के असली उद्देश्य समझाते हुए उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल अच्छे गायक के प्रदर्शन को निखारने के लिए होना चाहिए, ना कि गैर-गायकों को कलाकार बनाने के लिए।

सोनू ने खुद को बताया खुशकिस्मत

सोनू निगम ने आगे अपनी बात करते हुए कहा, 'जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पहले के दिनों में ऑटो-ट्यून के बिना गाना पड़ता था और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इसके बिना ही रियाज किया है। हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करता हूं।'

सोनू निगम का वर्कफ्रंट

सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में फिल्म 'बंटवारा 1947' के गाने 'तबस्सुम' को अपनी आवाज दी है। एआर रहमान द्वारा संगीतबद्ध और जावेद अख्तर द्वारा लिखित इस गाने को अली फजल, ईशा संधिर, करण देओल और कनिका कपूर जैसे अभिनेताओं पर फिल्माया गया है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है।

इंडस्ट्री छोड़ने के लिए खुद को तैयार कर लिया था

'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' यामी के करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। खास बात यह है कि फिल्म की सफलता के साथ यामी और निर्देशक आदित्य धर का रिश्ता भी मजबूत हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली।

यामी गौतम आज हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों शुमार है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दमदार अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब वह बॉलीवुड को अलविदा कहने का मन बना चुकी थी । उसने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म 'विक्की डोनर' से अपने करियर की शानदार शुरुआत के बावजूद उसे कई वर्षों तक ऐसे मौके नहीं मिले, जिनसे वह बतौर अभिनेत्री खुद को साबित कर पाती।

यामी ने 2012 में फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म सफल रही, लेकिन इसके बावजूद 'उसके करियर को वह रफ्तार नहीं मिल सकी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी ।

यामी के अनुसार, इंडस्ट्री में उसकी शुरुआत को 'अनकन्वेंशनल' माना गया, क्योंकि उसे पारंपरिक तरीके से लॉन्च होने वाली हीरोइन की तरह पेश नहीं किया गया था। उसका मानना है कि इस धारणा का असर उसके करियर पर भी पड़ा।

कई सालों तक अच्छे और चुनौतीपूर्ण किरदारों का इंतजार करने के बाद यामी का भरोसा डगमगाने लगा था।

उस दौर को याद करते हुए यामी ने कहा कि उसने खुद को बॉलीवुड से पूरी तरह अलग होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था । वह हिमाचल प्रदेश वापस लौटने के बारे में सोच रही थी, जहां उसके परिवार की जमीन है। उसने वहां एक बिल्कुल अलग जिंदगी शुरू करने की कल्पना भी कर ली थी।

यामी के अनुसार, उसके माता-पिता ने भी इस फैसले में उसका पूरा साथ दिया और उससे बस इतना कहा कि अगर वह घर लौटना चाहती है तो वे उसका स्वागत करेंगे।

दिलचस्प बात यह रही कि जिस वक्त यामी ने इंडस्ट्री में टिके रहने की जिद छोड़ दी, उसी वक्त उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया।

इसके बाद उसे 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' मिली और फिर 'बाला' जैसी फिल्मों ने उसके करियर को नई दिशा दे दी। 2019 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और यामी की अभिनय क्षमता को भी नए सिरे से पहचान मिली।

'उरी' ने बदल दी जीवन की दिशा

'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' यामी के करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में था। खास बात यह है कि फिल्म की सफलता के साथ यामी और आदित्य धर का रिश्ता भी मजबूत हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली ।

स्टार किड्स को बार- बार मौके मिलने से थी आह

यामी ने इंडस्ट्री में आऊटसाइडर होने की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। हालांकि, उसका कहना है कि परेशानी सिर्फ आऊटसाइडर होने की नहीं थी, बल्कि लगातार खुद को साबित करने की थी ।

उसने बताया कि कई बार उसे लगता था कि वह किसी खास भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वही मौका किसी ऐसे व्यक्ति को बार-बार मिल जाता था, जो पहले से फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित माहौल का हिस्सा था ।

यामी के अनुसार, सबसे ज्यादा निराशा इस बात से होती थी कि स्टारकिड्स को असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने और खुद को साबित करने के कई मौके मिल जाते हैं, जबकि इंडस्ट्री से बाहर से आने वाले कलाकारों को एक मौका हासिल करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है।

यामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उसे भी उतने मौके मिले होते, तो क्या वह एक अभिनेत्री के तौर पर और आगे नहीं बढ़ती ? उसके अनुसार, यही उसके संघर्ष का सबसे निराशाजनक हिस्सा था।

हालांकि, अब यामी को लगता है कि चीजें काफी बदल चुकी हैं। उसका मानना है कि आज दर्शक इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि कोई कलाकार कहां से आया है और इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि वह कितना अच्छा अभिनय करता है, उसकी फिल्म देखने लायक है या नहीं और वह अपने किरदारों का चुनाव किस तरह करता है । हालांकि, यामी अब अपने उस दौर को पीछे छोड़ चुकी है।

उसके लिए संघर्ष के उन वर्षों ने शायद उसे यह समझने में मदद की कि किसी कलाकार का सफर हमेशा सीधा नहीं होता ।

मेरा पहला जुनून है डांस : 'संदीपा धर'

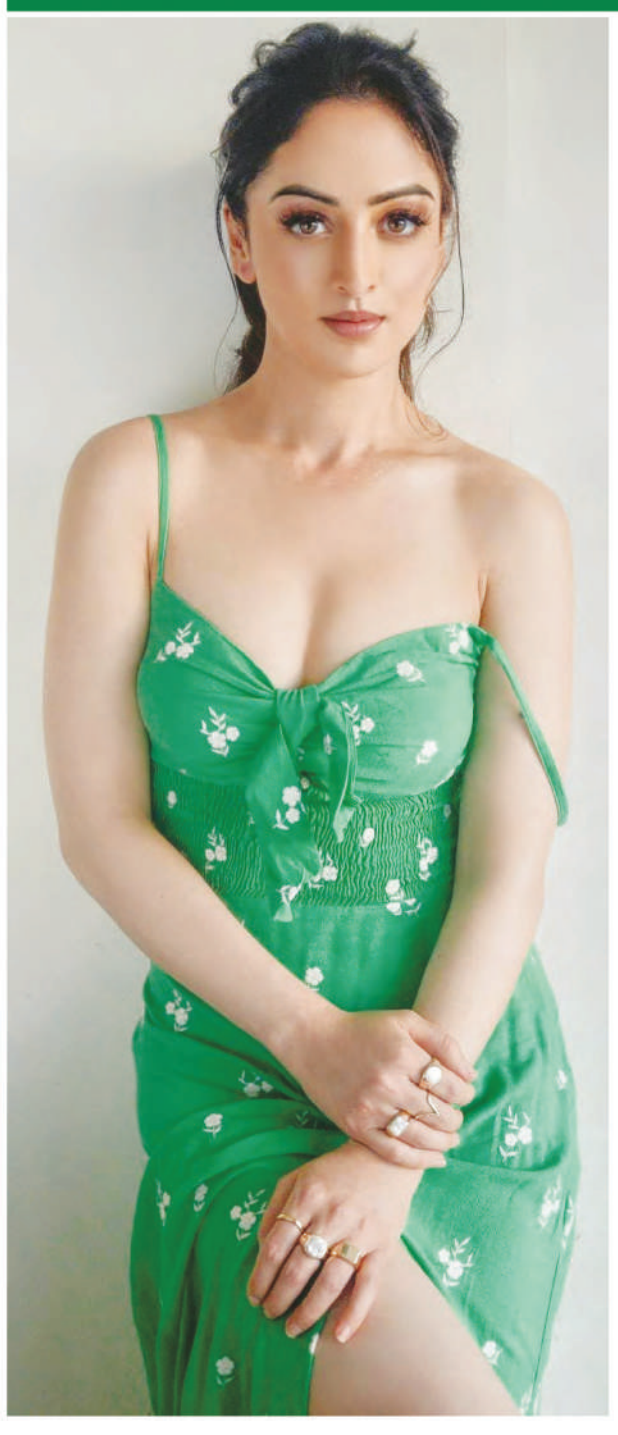

डांस उसके लिए खुद को व्यक्त करने का जरिया बना । जिंदगी में जब भी मुश्किल समय आया, डांस ने उसे संभाला।

संदीपा धर की जिंदगी में डांस का महत्व अभिनय से कहीं अलग और गहरा है । बचपन से ही डांस सीखने वाली संदीपा ने भरतनाट्यम के साथ-साथ कई अन्य डांस फॉर्म भी सीखे हैं। वह खुलकर कहती है कि उसका पहला जुनून डांसिंग है और उसे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वह एक्ट्रैस से बेहतर डांसर है।

उसके लिए डांस केवल स्टेज पर परफॉर्म करने या दर्शकों का मनोरंजन करने का माध्यम नहीं है ।

वह इसे अपने भावनात्मक संसार से जुड़ा हुआ मानती है। संदीपा बताती है कि वह बचपन से काफी शर्मीली रही है और डांस उसके लिए खुद को व्यक्त करने का जरिया बना ।

जिंदगी में जब भी मुश्किल समय आया, डांस ने उसे संभाला। गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो या कोई बुरा दौर-संदीपा के लिए डांस इन को बाहर निकालने का माध्यम रहा है।

उसका मानना है कि कला के साथ एक खास आध्यात्मिक रिश्ता होता है । वह डांस करते समय खुद को इतना डूबा हुआ महसूस करती है कि बाकी सारी चीजें भूल जाती है। उसके लिए डांस किसी मैडिटेशन (ध्यान - मनन) से कम नहीं और उसे लगता है कि इसके जरिए उसका भगवान से सीधा जुड़ाव बनता है।

यूं पैदा हुआ डांस का जुनून

संदीपा के डांस के सफर की कहानी में माधुरी दीक्षित का नाम बेहद खास है । बचपन में माधुरी के गानों और उसके डांस को देखकर ही संदीपा के मन में डांस सीखने की इच्छा पैदा हुई ।

'दीदी तेरा देवर दीवाना' और 'माए नी माए' जैसे गानों में माधुरी के डांस और एक्सप्रैशन ने संदीपा को इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी मां से कहा कि उसे भी ऐसा ही डांस करना है । इसके बाद मां ने उसे कम उम्र में ही भरतनाट्यम की क्लास में डाल दिया।

वह मानती है कि माधुरी के एक्सप्रैशन और ग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। उसके अनुसार, जिस तरह का डांस और अभिनय माधुरी और श्रीदेवी के दौर में देखने को मिलता था, वैसा जादू आज कम ही नजर आता है। संदीपा के लिए माधुरी सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि उसकी डांस प्रेरणा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक है कि किसी दिन उसे माधुरी के साथ डांस और स्टेज शेयर करने का मौका मिले।

अब कॉमेडी में दिखेगी संदीपा

डांस और ग्लैमर के बीच संदीपा अपने अभिनय करियर में भी नए प्रयोग कर रही है । उसकी अगली वैब सीरीज ' चुंबक ' जल्द रिलीज होने जा रही है। खास बात यह है कि इसके जरिए वह पहली बार कॉमेडी शैली में कदम रख रही है।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com